भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3156
उत्तर देने की तारीख 19 मार्च, 2025

बीएसएनएल कनेक्टिविटी का कमजोर होना

3156. श्री हमदुल्ला सईदः

क्या ***संचार*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार को विभिन्न क्षेत्रों में बीएसएनएल कनेक्टिविटी के कमजोर होने के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान बीएसएनएल के नेटवर्क और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार कितनी धनराशि आवंटित की गई है और कितनी परियोजनाएं शुरू की गई हैं; और
(ग) निजी दूरसंचार ऑपरेटरों के मुकाबले बीएसएनएल की प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) से (ग) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) विभिन्न सेवा-गुणवत्ता (क्यूओएस) पैरामीटरों के लिए बेंचमार्क की तुलना में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के कार्य-निष्पादन की नियमित रूप से निगरानी करता है। कार्य-निष्पादन निगरानी रिपोर्ट (पीएमआर) के अनुसार बीएसएनएल सेलुलर सेवाओं के अधिकतर क्यूओएस पैरामीटरों के नेटवर्क संबंधी बेंचमार्कों को पूरा कर रहा है।

इसके अलावा, बीएसएनएल के नेटवर्क और अवसंरचना सहित इसकी सेवाओं में सुधार लाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2019 में लगभग 69 हजार करोड़ रुपये के पहले पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी जिससे बीएसएनएल/एमटीएनएल की प्रचालन लागत में कमी आई। वर्ष 2022 में लगभग 1.64 लाख करोड़ रुपये का पुनरुद्धार पैकेज दिया गया। इसमें नए सिरे से

पूंजी निवेश करने, ऋण का पुनर्गठन, ग्रामीण टेलीफोनी के लिए व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण आदि पर ध्यान केंद्रित किया गया। वर्ष 2023 में सरकार ने लगभग 89 हजार करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ बीएसएनएल को 4जी/5जी स्पेक्ट्रम के आवंटन को मंजूरी दी। इन पुनरुद्धार पैकेजों के अलावा 6,982 करोड़ रुपये की अतिरिक्त पूंजीगत व्यय सहायता के लिए मंत्रिमंडल नोट को 07.02.2025 को मंजूरी दी गई है।

इन पैकेजों के परिणामस्वरूप बीएसएनएल ने वित्त वर्ष 2020-21 से प्रचालनगत लाभ अर्जित करना शुरू कर दिया है।

इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत पहल की तर्ज पर बीएसएनएल ने अखिल भारतीय तैनाती के लिए स्वदेशी रूप से विकसित 4जी साइटों हेतु क्रय आदेश दिया है। सितंबर 2023 से 4जी उपकरणों की आपूर्ति शुरू हो गई है और दिनांक 05.03.2025 की स्थिति के अनुसार कुल 83,629 4जी साइटें संस्थापित कर दी गई हैं और 74,123 साइटें ऑन-एयर हैं।

*****